I will get this matter enquired into the satisfaction of the hon. Member.

SHRI K. LAKKAPPA : Is there any scheme like that ?

SHRI HARINATHA MISRA : There is a comprehensive scheme. But I cannot say off-hand the practice which is being followed by the Orissa Government.

AN HON. MEMBER : I would like to know whether the scheme is applicable to cyclones.

SHRI HARINATHA MISRA : I told the hon. Member through you that the whole insurance scheme is a comprehensive one.

SHRI HARIHAR SOREN : From the statement it appears that the Central assistance given to Orissa for special livestock production programme is 1983-84 has been reduced to Rs. 5.350 lakhs as against Rs. 28.870 lakhs in 1980-81, Rs. 29.090 lakhs in 1981-82 and Rs. 56.585 lakhs in 1982-83 May I know what is the reason for the decline in Central assistance to Orissa under the above programme and whether the Central assistance is proposed to be enhanced in 1984-85 in view of the greater need of coverage to be given to Orissa under the above programme ?

SHRI HARINATHA MISRA : The figures supplied by the Orissa Government are as follows...

AN HON. MEMBER : He wants about Central assistance.

SHRI HARINATHA MISRA : I am coming to the point. Towards the end of 1982-83, it was found that accumulated unspent funds to the tune of Rs. 70 lakhs were with the Orissa Government Naturally when they had so much of funds, we thought that the Orissa Government should be warned. Rs. 5.35 lakhs related to staff expenditure and maintenance of the establishment only were sanctioned.

Further, I may point out that the Orissa Government were warned as late as in February last they should show better performance. In view of what the hon. Member has said and in view of the reports received from my own officers, I am thinking of deputing a responsible senior officer to make an on the spot enquiry and to submit a comprehensive repots. Of course, we want the programme to contiuue and to catch momentum. With a view to ensuring that, we want to send this officer to the spot.

SHRI SANTOSH MOHAN DEV : In the national press it has been published that the hon. Minister has said to a team of high officials that in view of the fact that most of the subsidy is misused, Government is thinking of keeping the subsidy in bank as fixed deposit and using it as a security for repayment of loan which is given under the various Central schemes. May I know whether it is a fact and if so, what is the progress on that ?

SHRI HARINATHA MISRA : This question relates to the Orissa Government and also to a particular programme. I cannot say anything on what has been published in newspapers in the all India context.

Performance of National Seeds Corporation

*947. SHRI RAMAVTAR SHASTRI :
SHRI VIJAY KUMAR YADAV : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government propose to consititute a high level committee to go into the functioning and performance of National Seeds Corporation;

(b) whether Government propose to have a thorough auditing of balance sheet for the year 1982-83 by tribunal of auditors, approved by the Board on 3 November, 1983, to find out any manipulations;

(c) the achievement of production and sales in comparison to their targets approved by the Board for the year 1982-83 in its preceding meetings and steps taken to fix responsibilities on defaulting officials; and

(d) whether a thorough inquiry, in all purchases made through global and local tenders by National Seeds Corporation for itself and for the State Seeds Corprations and other institutions under the World Bank aided National Seeds Projects, is proposed to be held ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) The target for production of seeds by National Seeds Corporation Ltd. for 1982-83 was 8.83 lakh quintals against which the actual production was 6.65 lakh quintals. The target for marketing for the same year was 4.72 lakh quintals against which the achievement was 4.18 lakh quintals. The shortfall in production was due to severe drought condition all over the country resulting in lower production by the State Seed Corporations. In the case of marketing, the shortfall was due to inadequate availability as a result of damage of wheat seeds because of untimely rains during the preceding year and less supply by the State Seeds Corporations compared to the programme given by National Seeds Corporation Ltd.

(d) No, Sir.

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, "जी नहीं" कह कर के इन्होंने राष्ट्रीय बीज निगम के अन्दर जो धांधले बाजियां चल रही हैं या जो भ्रष्टाचार है, उनको छिपाने का प्रयास किया है। चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर जब से आए हैं तब से उस संगठन के अन्दर भेद भाव की नीति बरती जा रही है और शक्तियों के दुरुपयोग की बजह से वहां के कर्मचारियों में असंतोष है। इसकी वजह से वहां पर भ्रष्टाचार या कदाचार पनप रहा है। क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी मिली है। इस तरह की चीजें अखबारों में भी निकली हैं और लोगों से भी पता चला है। इस बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह गलत बात है। चेयरमैन सीड्स कारपोरेशन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए उसका प्रोडक्शन काफी बढ़ा है।

श्री रामावतार शास्त्री : प्रोडक्शन कहां बढ़ा है ? आपने जवाब में नहीं बताया है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : पिछले दस सालों में 200 टाइम प्रोडक्शन बढ़ा है। मैं जवाब में बता देता तो आप सप्लीमेंट्री कैसे पूछते। प्रोडक्शन काफी बढ़ा है और पिछले 20 सालों का अगर देखें तो 2000 टाइम प्रोडक्शन बढ़ा है। वहां का काम अच्छा चल रहा है इसलिए इतना प्रोडक्शन बढ़ा है। चेयरमैन अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। यह बात हो सकती है कि कुछ कर्मचारी होते हैं जो गलत काम करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कार्मचारी नहीं कर्मचारी।

श्री योगेन्द्र मकवाना : You kindly bear my Hindi.

जहां इन लोगों ने गलत काम किए हैं वहां चेयरमैन ने एक्शन भी लिए हैं। मैंने भी डायरेक्शन दिए हैं—'You should take action against such employees.' ऐसे लोग ही मेंबर्स के पास जाकर के गलत इनफरमेशन देते हैं और उसी गलतफहमी की वजह से माननीय सदस्य यह बात कह रहे हैं। यह गलत है।

श्री रामावतार शास्त्री : जो इनफरमेशन मिलेगी, उसी को तो हम कहेंगे। आसमान

से तो इन्फारमेशन लाएंगे नहीं। अब उसका खण्डन या मण्डन करना आपका काम है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मेंबर पर आक्षेप लगाया गया है। हमें जो जानकारी उपलब्ध होती है उसी के आधार पर हम यहां बोलते हैं। मंत्री महोदय यह नहीं कह सकते कि गलत जानकारी के आधार पर सवाल पूछा गया है। वे यह कह सकते हैं कि आपकी जानकारी गलत है।

अध्यक्ष महोदय : यही कह रहे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : मुझे जो जानकारी मिली है—वही बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, व्याकरण के हिसाब से आपने सुधार कर दिया।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने जो सुना है, उसी को कह रहा हूं। अखबारों में भी खबरें निकलती हैं।

अध्यक्ष जी, दूसरा सवाल मेरा है कि देश के अंदर ग्लोबल टेंडर आपका बीज निगम करता है। इस मामले में भी शिकायतें मिली हैं। इसमें भी गोलमाल या घपला है। इसलिए मैंने इस सवाल के जरिए मांग की है कि इसकी थारो इन्क्वारी होनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि पैकेजिंग में कहीं गड़बड़ है या पैसा बनाने की कोशिश की गई है। इन्क्वायरी करवाने से आप क्यों घबराते हैं? अगर इस तरह की शिकायत हो तो इंक्वारी करने से साफ हो जाएगा। यदि गलत शिकायत है तो मालूम हो जाएगा और सही है तो उस बात को दुरूस्त किया जाना चाहिए। इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि आप के यहां क्या कानून है?

श्री योगेन्द्र मकवाना : अगर कोई स्पेसिफिक बात हो ी तो उस पर इंक्वायरी करने के लिए मैं हां कर सकता था। लेकिन जो वेग एलीगेशन्स या कंपलेंट्स हैं, वह स्पेसिफिक नहीं है जिन पर इंक्वायरी की जाए। कुछ स्पेसिफिक इंस्टांस माननीय सदस्य देंगे तो उस पर अवश्य जांच करवायेंगे। लेकिन स्पेसिफिक होना चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री : बीज का जो पैकेट होता है, उसमें गड़बड़ है।

...(व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : क्या गड़बड़ है?

श्री रामावतार शास्त्री : पैसे कमाए गए हैं और कितना खुलकर बताऊं?

श्री योगेन्द्र मकवाना : आप खुलकर बताइए।

श्री रामावतार शास्त्री : आपके अधिकारियों ने पैसे कमाए हैं जिसकी जानकारी अपके चेयरमैन और मैनेजिंग डाइरेक्टर को है। इस मामले में इंक्वायरी करने की जरूरत है। आप कहते हैं कि इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है। जो गड़बड़ हुई है, उसको सामने लाने के लिए इंक्वायरी जरूरी है। ग्लोबल टेण्डर के बारे में बताइए?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने बार-बार कहा है कि किसी गलतफहमी की वजह से ही माननीय सदस्य कह रहे हैं। जो 17 टेण्डर आज तक हम लोगों ने इन्वाइट किए थे, उसमें से 9 लोकल थे और 8 ग्लोबल टेण्डर थे। 13.34 करोड़ रुपये के टेण्डर थे। उसमें कुछ ऐसे भी थे जिसमें लोअर प्राइस कोट की गई थी। लेकिन उनके इक्वीपमेंट सही नहीं थे इसलिए हमने हायर

प्राइस वाले को लिया। जब हम टेण्डर इन्वाइट करते हैं तो उसके बाद दो कमेटी होती है जिनमें इवेल्यूएशन के लिए भेजते हैं। एक तो इवेल्यूएशन कमेटी होती है जो टेण्डर का इवेल्यूएशन करती है। एक सब-कमेटी होती है। वह हर चीज की छान-बीन करती है। जो सही होता है, उसको लेने की इजाजत देती है। उसमें कभी ऐसा भी होता है कि जिसका सब-स्टेण्डर्ड माल हो, व बहुत लो प्राइस कोट किया हुआ तो उसको हम नहीं लेते हैं क्योंकि उससे नुकसान होता है। इसलिए, हायर-प्राइस का लेना पड़ता है। इससे गलतफहमी यह होती है कि हायर-प्राइस वाले को क्यों लिया जबकि कम प्राइस वाले भी थे ? अच्छा माल न होने की वजह से हायर-प्राइस का एक्सेप्ट करना पड़ता है।

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के जरिए से कई तरह की मांग राष्ट्रीय बीज निगम के सिलसिले में की गई है। पूरे देश में किसानों को राष्ट्रीय बीज निगम बीज सप्लाई करता है, उसकी चर्चा हुई है और इसके अलावा जो इसके अन्दर तरह-तरह की खराबियां पली हुई हैं, उसकी चर्चा भी अभी शास्त्री जी ने की है। मंत्री महोदय ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे किसी कर्मचारी पर कार्यवाही की गई हो जिसकी वजह से यह प्रश्न करवाया गया है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर के सवाल इसके अन्दर पूछे गए हैं। चाहे उसकी परफार्मेंस या फंक्शनीग का सवाल हो या उसकी बैलेंस-शीट में जो मैनीपुलेशन की चर्चा की गई, उसकी जांच-पड़ताल की बात हो। सभी मामलों में मंत्री महोदय ने उससे इन्कार किया है। अखबारों में जो रिपोर्ट आई है, उससे एक शक जाहिर होता है कि इतना महत्वपूर्ण कारपोरेशन है। जिसका सम्बन्ध देश के विकास से गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है। अगर उसके फक्शनींग के मामले में गड़बड़ी होती है तो उससे पूरे राष्ट्र को नुकसान होता है। लेकिन, मंत्री महोदय ने तो किसी तरह की जांच-पड़ताल से इन्कार किया है।

इसमें 3 दिसम्बर, 1983 के बोर्ड के द्वारा लिए गए फैसले का जिक्र किया गया है, जिसमें मैनीपुलेशन तथा बैलैंस शीट आदि की चर्चा आई है। मैं जानना चाहता हूं कि बोर्ड की मीटिंग में क्या फैसला लिया गया और उसके ऊपर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : बोर्ड ने क्या फैसला अपनी मीटिंग में लिया, उसको यहां बतलाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन मेरे पास फीगर्स हैं और में उनके आधार पर कहना चाहता हूं आपने जो कुछ कहा है, गलत है। इस समय वहां जो मैनेजिंग डाइरैक्टर-कम-चेयरमैन हैं, वे पिछले तीन-चार साल से काम कर रहे हैं और उनके पीरियड में इस कारपोरेशन का प्रोडक्शन बढ़ा है। यदि आप उसकी फीगर्स को देखें-तो वर्ष 1963-64 में जहां 428 क्वंटल उत्पादन होता था, वर्ष 1973-74 में बढ़कर वह 369 हजार क्विंटल हो गया, वर्ष 1982-83 में वह बढ़ कर 659 हजार क्विंटल हो गया, वर्ष 1983-84 में वह बढ़ कर 830 हजार क्विंटन हो गया तथा वर्ष 1984-85 में बढ़कर वह 1.4 मिलियन क्वंटल हो गया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कार्पोरेशन में दिन-प्रति-दिन उत्पादन बढ़ता ही जा रहा है। जहां तक इसके लक्ष्य और टर्न ओवर का प्रश्न है, वर्ष 1963-64 में इसका टर्न-ओवर 356 हजार था जो 1983-84 में बढ़कर 220 मिलियन हो गया है। जहां तक टार्गेट और एचीवमैंटस का सम्बन्ध है, उसके बारे में मैंने पहले ही अपने उत्तर में बताया है कि हम स्टेट सीड फार्म

से प्रोग्रामिंग करते हैं । वर्ष 1982-83 में जो शार्टफाल आया है, उसके पीछे वर्स्ट ड्रौट ऑफ दी सैन्चुरी का कारण है । यदि उस साल कमी आई तो वह कोई बड़ी बात नहीं है । यदि आप प्रोडक्शन की फीगर्स चाहें तो में एचीवमैंट आदि की फीगर्स क्राप-वाइस बता सकता हूं, यदि आप चाहें तो मैं उनको टेबल पर भी रख सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप उनको टेबल पर ही रख दीजिए क्योंकि यहां पढ़ने से काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं उनको टेबल पर रख देता हूं । लेकिन आपका यह कहना गलत है कि यह कार्पोरेशन अच्छी तरह से नहीं चल रही है । जहां तक क्वालिटी की बात है वर्ष 1982-83 में 44 हजार सैम्पल्स को हमारी क्वालिटी कन्ट्रोल लैबोरेटरी में टैस्ट किया गया । उससे जाहिर होता है कि क्वालिटी कन्ट्रोल के मामले में हम पूरी तरह जागरूक हैं और यह कार्पोरेशन अच्छा काम कर रहा है ।

श्री विजय कुमार यादव : सर, बोर्ड ने क्या फैसला लिया और उसके आडिट के बारे में जो मेरे प्रश्न थे, उनका उत्तर नहीं आया ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : इस कर्पोरेशन का आडिट चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस करते हैं और ससको कम्पट्रोलर और औडिटर ऑफ इण्डिया द्वारा रिव्यू किया जाता है । उस रिपोर्ट में कोई बुरी बात सामने अभी तक नहीं आई है । पता नहीं आप कैसे इस निषकर्ष पर पहुंच गये कि यह कार्पोरेशन ठीक नहीं चल रहा है । इस कार्पोरेशन का आडिट हम पार्लियामेंट के सामने समय समय पर लाते रहते हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं कि यह कैसी चल रही है ।

Forest cover Disappearing in Rajasthan

*948. SHRI VIRDHI CHANDER JAIN : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the forest cover in many districts of Rajasthan is on the verge of disappearing creating a fuel wood famine in the area and disturbing ecological balance;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have taken up the matter with Rajasthan Government to take effective steps against destruction of forest wealth of the State; and

(d) if so, the outcome thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENERA MAKWANA) : (a) According to information received from the State Government, the forest cover is not on the verge of disappearing in any district of Rajasthan.

(b) Question does not arise.

(c) Prime Minister herself has been writing to the Governors and the Chief Ministers of all the State Governments including Rajasthan for preservation of forest wealth. Forest (Conservation) Act, 1980 has been passed to regulate diversion of forest area for non-forestry purposes. Guidelines have also been issued for preservation of forest. Under the New Twenty Point Programme unprecedented thrust has been imparted to tree plantation and social forestry on a massive scale.

(d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The State Government has initiated following steps for better protection of forest and increase of forest wealth ;